



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 334]

No. 334]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 1989/आषाढ़ 6, 1911

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 1989/ASADH 6, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

प्रधिमूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 1989

अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर नियम 4/89

सा कानि 646(अ).—केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1989 (1989 का 13) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर नियम, 1989 है।

(2) ये 1 जुलाई 1989 को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाएँ—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अथवा प्रोक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से वित्त अधिनियम, 1989 (1989 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) “सीमाशुल्क न्यायक कलक्टर” से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 4 के अधीन इस रूप में नियुक्त किया गया है और जिसकी अधिकारिता उक्त अधिनियम के अधीन दिल्ली पर है;

(ग) “केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी” का वही अर्थ है जो उक्त केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम में है;

(घ) “सीमाशुल्क कलक्टर” से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 4 के अधीन सीमाशुल्क कलक्टर या अपर सीमाशुल्क कलक्टर, दिल्ली के रूप में नियुक्त किया गया है;

(ङ) “सीमाशुल्क कलक्टर (अपील)” से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 4 के अधीन इस रूप में नियुक्त किया गया है;

(च) “सीमाशुल्क अधिनियम” से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) अभिप्रेत है;

(छ) “सीमाशुल्क अधिकारी” का वही अर्थ है जो उसका सीमाशुल्क अधिनियम में है;

(ज) “कर” से अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन उद्घृष्ट अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर अभिप्रेत है;

(झ) “खजाना” से अभिप्रेत है—

(i) सीमाशुल्क मदद खजाना, या

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955

(1955 का 23) की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक, या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तर्ण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तर्ण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 3 के अधीन गठित कोई बैंक जिसमें इस निमित्त केन्द्रीय सरकार का खाता हो।

3. कर का संग्रहण—अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत बाहक द्वारा कर का संग्रहण अन्तर्देशीय यात्रा पर पोता-रोहण करने के लिए किसी यात्री या उसके अधिकर्ता को टिकट जारी करने के समय किया जाएगा:

परन्तु ऐसे मामले में जहां किसी कारणों से कर का संग्रहण टिकट जारी किए जाने के समय नहीं किया जाता है वहां कर का संग्रह किसी यात्री के अन्तर्देशीय यात्रा पर जाने से पूर्व बाहक द्वारा किया जाएगा।

4. कर का प्रतिदाय—(1) ऐसे मामले में जहां यात्री टिकट का नया कर चुकने के पश्चात् अन्तर्देशीय यात्रा पर न जाने का विनिश्चय करता है वहां ऐसी यात्रा के लिए संग्रहण की गई कर की रकम का प्रतिदाय उसको या उसके अधिकर्ता को पूर्ण रूप में बाहक द्वारा उसी रीति में किया जाएगा। जैसे किराए का प्रतिदाय किया जाता है।

(2) किसी अन्य मामले में कोई यात्री या उसका अधिकर्ता बाहक की उसके द्वारा संवत् किए गए किसी कर का प्रतिदाय करने का दावा करने के लिए वह कर के संदाय की तारीख से दो वर्ष का कालावधि की समाप्ति के पूर्व या ऐसी यात्रा के अंतिम दिन, जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है, जो भी पश्चात्पूर्ति हो, ऐसे कर के प्रतिदाय के लिए बाहक को आबेदन भेज सकेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन किसी आबेदन की प्राप्ति पर, यदि बाहक का समाधान हो जाता है कि संवत् किए गए कर की रकम का गलत रूप से संग्रहण किया गया है और उसका प्रतिदाय किया जाना चाहिए तो वह रकम का यात्री या उसके अधिकर्ता को तदनुसार प्रतिदाय कर सकेगा।

(4) जहां कोई बाहक कर के रूप में किसी रकम का खजाने में संदाय कर चुकने पर, पाता है कि वह संदाय गलत रीति में किया गया है, तो वह ऐसी रकम के प्रतिदाय के लिए सहायक सीमाशुल्क कलक्टर को उस कर के, जिसके संबंध में प्रतिदाय का दावा किया जाता है, संदाय की तारीख से दो वर्ष की छात्रावधि की समाप्ति के पूर्व आबेदन कर के दावा कर सकेगा।

(5) यदि उपनियम (4) के अधीन किसी आबेदन की प्राप्ति पर सीमाशुल्क सहायक कलक्टर का समाधान हो जाता है कि गलत रीति से संवत् किए गए कर की रकम का प्रतिदाय किया जाना चाहिए, तो वह तदनुसार आदेश कर सकेगा।

5. कर का असंदाय या न्यून संदाय:—(1) जहां किसी शोधक कर का यात्री या उसके अधिकर्ता द्वारा किसी भी कारण से, खजाने में संदाय नहीं किया गया है या पूर्णतः संदाय नहीं किया गया है, तो वहां बाहक, यात्रा की अंतिम तारीख से दो वर्ष के भीतर यात्री या उसके अधिकर्ता से रकम का संदाय करने के लिए निश्चित मांग कर सकेगा।

(2) जो बाहक द्वारा संग्रहीत किए गए किसी कर का किसी कारण से नियम 6 के अधीन खजाने में संदाय नहीं किया गया है या पूर्णतः संदाय नहीं किया गया है अथवा नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन गलत रीति से प्रतिदाय किया गया है वहां सीमाशुल्क सहायक कलक्टर, संग्रहीत तारीख से दो वर्ष की छात्रावधि के भीतर सम्बन्धित बाहक पर उससे यह हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करने हुए सूचना की तामील कर सकेगा कि उसे सूचना में विनिश्चित रकम का संदाय क्यों नहीं करना।

परन्तु जहां किसी का संदाय नहीं किया गया है या पूर्ण रूप से संदाय नहीं किया गया है अथवा बाहक द्वारा दुरुभिसंधि के कारण या जानबूझ कर किमी गलत कथन या तथ्यों को बाने के कारण उसका गलत रीति से प्रतिदाय किया गया है वहां इस उपनियम के उपबन्ध जैसे ही प्रभावी होंगे मानो "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे गए हो।

(3) सीमाशुल्क सहायक कलक्टर उस बाहक द्वारा जिन पर उपनियम (1) के अधीन सूचना की तामील की गई है किए गए आबेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् ऐसे बाहक द्वारा सदन कि जाने वाले कर की रकम का (जो सूचना में विनिश्चित रकम से अधिक नहीं होगी) अवधारण करेगा और तदुपरि ऐसा बाहक इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा।

(4) उपनियम (2) के प्रयोजन के लिए "संग्रहीत तारीख" पर से अभिप्रेत है—

(क) उस दशा में जहां कर का संदाय नहीं किया गया है या पूर्णतः संदाय नहीं किया गया है वहां उस अन्तर्देशीय यात्रा यात्रा के, जिसमें यथास्थिति, असंदाय या न्यून संदाय संबंधित है, प्रारंभ की तारीख या ऐसी तारीख जिन पर बाहक इन नियमों के अधीन संग्रहीत विवरणी फाईल कर देता है, इनमें से जो भी पश्चात्पूर्ति हो,

(ख) उस दशा में जहां कर का गलत रीति में नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन प्रतिदाय किया गया है, वहां वह तारीख, जिसको प्रतिदाय किया गया था।

6. खजाने में संवत् किया जाने वाला कर—किसी बाहक द्वारा किसी मास में संग्रहीत कर का संदाय ऐसे बाहक द्वारा उस मास की समाप्ति से साठ दिन की समाप्ति के पूर्व खजाने में जमा किया जाएगा।

परन्तु सीमाशुल्क कलक्टर दर्शित किए गए पर्याप्त हेतुक, पर, और किसी बाहक द्वारा अपनाई गई किसी लेखा पद्धति का ध्यान रखते हुए, ऐसे बाहक को नब्बे दिन से अधिक की और कालावधि के भीतर कर का संदाय करने के लिए अनुज्ञान कर सकेगा।

7. संग्रहीत कर प्राप्ति से संबंधित विवरणी—प्रत्येक बाहक जिसमें नियम 6 के अधीन खजाने में कर संदाय करने की अपेक्षा की जाती है प्रत्येक मास की बाबत उस मास के अंत में साठ दिन की समाप्ति के पूर्व सीमाशुल्क कलक्टर के सामने संग्रहीत कर की रकम, प्रतिदाय की गई रकम और खजाने में सदन की गई रकम दर्शित करने वाले इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में विवरणी फाईल करेगा।

परन्तु सीमाशुल्क कलक्टर, किसी बाहक द्वारा अपनाई गई किसी लेखा पद्धति का ध्यान रखते हुए, ऐसे बाहक को नब्बे दिन से अधिक की और कालावधि के भीतर ऐसी विवरणी फाईल करने के लिए अनुज्ञान कर सकेगा।

8. बाहक द्वारा अभिलेखों का परिरक्षण—कर के सप में संग्रहीत रकम जिन खजानों, बालानों या बाउचरों के द्वारा खजाने में सदन की गई है, उनकी प्रतियां, ऐसी अन्तर्देशीय यात्रा में संबंधित विवरणियां और सभी अन्य दस्तावेजों बाहक द्वारा उस तारीख से जिसका ऐसे बालान, बाउचर, विवरणी या अन्य दस्तावेज तैयार किए गए थे, पांच वर्ष की कालावधि तक परिरक्षित रखे जाएंगे।

परन्तु सीमाशुल्क कलक्टर लिखित आदेश द्वारा और उसमें अभिलिखित किए जाने वाले कारणों में किसी बाहक से किसी ऐसे बालान, बाउचर, विवरणी या अन्य दस्तावेज की प्रति पांचवर्ष की उक्त अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए परिरक्षित करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा बाहक, जिसके संबंध में ऐसा आदेश किया गया, ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा।

9. जस्तियों का न्यायनिर्णयन—प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 46 के अधीन शास्ति का दावा है, ऐसी शास्ति सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा न्यायनिर्णयन की जा सकेगी

10 शास्त्रियों के उद्धरण के पूर्व हेतुक दक्षित करने के लिए सूचना का जारी किया जाता—किसी व्यक्ति पर कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला को आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे व्यक्ति को

(क) त्रिम आधार पर शास्ति अधिरोपित करना प्रमाणित है, उसे बताते हुए लिखा कि में सूचना नहीं दे दी जाती है..

(ख) ऐसे व्यक्तिगत समय के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, सूचना में उल्लिखित शास्ति के अधिरोपण के आधारे के विरुद्ध लिखित अप्रत्याशित करने के लिए अवसर नहीं दिया जाता है;

(ग) मामले में सुनवाई के लिए व्यक्तिगत अवसर नहीं दिया जाता है.

परन्तु खंड (क) में निर्दिष्ट कोई सूचना, और खंड (ख) में निर्दिष्ट अप्रत्याशित संबंधित व्यक्ति की प्रेरणा पर मौखिक हो सकेगा.

11. अपील—सहायक सोमाशुल्क कलक्टर द्वारा इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन पारित किसी विनिश्चय या आदेश में व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय या आदेश की संसूचना को तारीख से तीन मास के भीतर सोमाशुल्क कलक्टर (अपील), दिल्ली, को अपील कर सकेगा:

परन्तु अपील प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी का तीन मास का पूर्वोक्त कालबाधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह उस मास को प्रतिरिक्त अवधि के भीतर उसे पेश करने का अनुज्ञा द सकेगा।

(2) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यदि वह ऐसा चाहे तो और ऐसी आब करने के पश्चात्, जो आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उस विनिश्चय या आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट करते हुए, उचित करने के लिए या रद्द करने के लिए आदेश पारित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे:

परन्तु अपील प्राधिकारी द्वारा किया शास्ति में वृद्धि करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा.

परन्तु यह और कि जहाँ अपील प्राधिकारी की यह राय है कि नियम 6 के अधीन खजाने में किसी कर का संवाय नहीं किया गया है या पूर्णतः संवाय नहीं है अथवा नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन गलत रूप से प्रतिदाय किया गया है वहाँ जब तक अपीलार्थी को प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध नियम 5 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय को परिमीमा के भीतर हेतुक दक्षित करने के लिए सूचना नहीं दे दी जाती है, ऐसे कर का संवाय करने के लिए निवेश देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

12. कलक्टर को पुनरीक्षण की शक्तियाँ—सोमाशुल्क कलक्टर स्व-प्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे किसी विनिश्चय या आदेश का वैधता या औचित्य के धारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए किसी कार्यवाहियों के समिलेख को, जिसमें उसके अधीनस्थ किसी सोमाशुल्क अधिकारी ने अधिनियम या इन नियमों के अधीन कोई विनिश्चय या आदेश (जो नियम 11 के अधीन अपील में पारित आदेश नहीं है) पारित किया है, मांग सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे:

परन्तु किसी शास्ति को वृद्धि करने वाला कोई आदेश इस नियम के अधीन तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक प्रस्तावित आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति को उसके विरुद्ध हेतुक दक्षित करने का अनुचित अवसर न दे दिया गया हो:

परन्तु यह और कि जहाँ सोमाशुल्क कलक्टर को यह राय है कि खजाने में नियम 6 के अधीन किया कर का कोई संवाय नहीं किया गया है या पूर्ण रूप से संवाय नहीं किया गया है अथवा नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन गलत रूप से उसका प्रतिदाय किया गया है

वहाँ ऐसे कर के संवाय के लिए निवेश देने वाला कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्ति का नियम 5 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय की परिमीमा के भीतर उसके विरुद्ध हेतुक दक्षित करने के लिए कोई सूचना नहीं दी जाती है।

(2) किसी विनिश्चय या आदेश के संबंध में इस नियम के अधीन कोई कार्यवाही ऐसे विनिश्चय या आदेश का तारीख से एक वर्ष को कालबाधि को समाप्ति के पश्चात् संस्थित नहीं का जाएगा।

(3) सोमाशुल्क अधिनियम को धारा 4 के अधीन सोमाशुल्क अपर कलक्टर के रूप में नियुक्त कोई सोमाशुल्क अधिकारी इस नियम के अधीन पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम नहीं होगा।

13. केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनरीक्षण:—(1) केन्द्रीय सरकार स्व-प्रेरणा से या नियम 11 अथवा नियम 12 के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा व्यक्ति किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे आदेश का वातिल या उदात्तरित कर सकेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आवेदन उस अवधि की, जिसके विरुद्ध आवेदन किया जा रहा है, आवेदन की संसूचना का तारीख छः मास के भीतर किया जाएगा.

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को पर्याप्त कारण से उक्त उदात्तरित कालबाधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने से निवारित किया गया था तो वह उस प्रतिरिक्त छः मास का अवधि के भीतर आवेदन को प्रस्तुत करने का अनुज्ञा दे सकेगी।

(3) इस नियम के अधीन शास्ति का वृद्धि करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक प्रस्तावित आदेश से प्रभावित व्यक्ति का वातिल या उदात्तरित किए जाने के लिए इच्छित आदेश की तराख से एक वर्ष के भीतर उसके विरुद्ध हेतुक प्रस्तुत करने को सूचना नहीं दी जाती है।

(4) जहाँ केन्द्रीय सरकार को यह राय हो कि खजाने में नियम 6 के अधीन किया कर का संवाय नहीं किया गया है या उसका पूर्णतः संवाय नहीं किया गया है अथवा नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन गलत रूप से उसका प्रतिदाय किया गया है, वहाँ ऐसे कर का संवाय करने के लिए निवेश देना वाला आदेश इस नियम के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति को नियम 5 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट समय की परिमीमा के भीतर हेतुक दक्षित करने के लिए सूचना नहीं दे दी जाती है।

14. सरकार का शोध्य रकमों का वसूली—जहाँ अधिनियम के अध्याय 5 के अधीन किसी व्यक्ति से मांगा गया कोई कर या किसी व्यक्ति द्वारा संवेय कोई शास्ति संवत् नहीं का गई है वहाँ सोमाशुल्क सहायक कलक्टर अपने द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जिसमें शोध्य रकम विनिर्दिष्ट की जाएगी, तैयार करेगा और उसे जिले के कलक्टर को भेजेगा जिसमें उक्त व्यक्ति संपत्ति का स्वामी है या निवासी करता है या कारदार बनाता है और उक्त कलक्टर ऐसे प्रमाणपत्र का प्राप्ति पर उक्त व्यक्ति से उक्त विनिर्दिष्ट रकम को वसूलने के लिए उसे ही प्रसार होगा वाने वह मू-राजस्व को बकाया है।

15. निरीक्षण की शक्ति:—(1) सोमाशुल्क के राजपत्रित अधिकारी के इस निमित्त विशेष या साधारण आदेश द्वारा प्राधिकृत प्रत्येक सोमाशुल्क अधिकारी को यह प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजन के लिए कि इस अधिनियम या इन नियमों का प्रयोजनों का अनुपालन किया गया है या नहीं, किसी समुचित समय पर बाहक के परिसर में प्रवेश करने की और वहाँ पाए गए किसी व्यक्ति से, जो तत्समय उसका सारसाधक है, किन्हीं लेखा-बहिषा, विवरणियों या अन्य दस्तावेजों को उनके समक्ष उसके निरीक्षण के लिए पेश करने और उसे ऐसी अन्य जानकारी देने को प्रवेष्टा करने की शक्तियाँ होंगी जिनका वह यह विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए कि

या इन नव नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है या नहीं, व्यक्तिगत रूप से अपेक्षा करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसे अधिकारी को अस्तवैशेष याज्ञा पर यात्रियों को बहुत करने में लगे किसी वायुयान पर पहुँचने की स्वतंत्रता हो होगी और फलक में के किसी व्यक्ति से उक्त प्रयोजन के लिए उपरोक्त दस्तावेजों में से किसी का प्रस्तुत करने और उपरोक्त जानकारी देने की अपेक्षा करने की शक्तियाँ होंगी।

16. वायुयान या परिवार को तलाशों की शक्ति : यदि सीमाशुल्क के किसी ऐसे अधिकारी के पास जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर की शक्ति से नीचे का न हो, यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई दस्तावेज जो उसकी राय में इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में उपयोगिता संगत होगा, किसी वायुयान या वाहक के किसी परिवार में गुप्त रूप से छिपा के रखा गया है तो सीमाशुल्क या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारियों में से किसी अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों को तलाशों लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

प्रारूप

1. वाहक का नाम :
2. मास/कालावधि (जिससे यह :
विबरणी से संबंधित है)
3. मास/कालावधि के दौरान :
संग्रहित कुल रकम
- 4 मास/कालावधि के दौरान
प्रतिवाय की गई रकम
5. संग्रहित कुल रकम (3)-(4):
6. बाजाने में संवत् की गई रकम:

[स 4/आई.ए.टी.टी/१९८९-का. सं. 348/2/१९८९-टी. आर. यू.]

के. एल. दत्ता, उप सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 1989

No. 4/89-INLAND AIR TRAVEL TAX RULES

G.S.R. 646 (E).—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Finance Act, 1989 (13 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Inland Air Travel Tax Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the 1st day of July, 1989.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Finance Act, 1989 (13 of 1989);

(b) “Assistant Collector of Customs” means an officer appointed as such under section 4 of the Customs Act having jurisdiction under the said Act over Delhi;

(c) “Central Excise Officers” has the same meaning as in the Central Excises and Salt Act, 1944;

(d) “Collector of Customs” means an officer appointed under section 4 of the Customs Act as Collector of Customs, Delhi or Additional Collector of Customs, Delhi;

(e) “Collector of Customs (Appeals)” means an officer appointed as such under section 4 of the Customs Act;

(f) “Customs Act” means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(g) “Officers of Customs” has the same meaning as in the Customs Act;

(h) “tax” means the inland air travel tax leviable under Chapter V of the Act;

(i) “treasury” means—

(i) the Customs House treasury; or

(ii) The Reserve Bank of India constituted under section 3 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), or any branch of the State Bank of India constituted under section 3 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955), or a bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), or under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), wherein the Central Government has an account in this behalf.

3. Collection of tax.—The tax shall be collected by a carrier authorised under sub-section (2) of section 42 of the Act at the time of issuing a ticket to a passenger or his agent for embarking on inland journey :

Provided that in a case where due to some reasons tax is not collected at the time of issuing a ticket, the tax shall be collected by the carrier before a passenger embarks on inland journey.

4. Refund of tax.—(1) In a case where a passenger, having purchased a ticket, decides not to embark on an inland journey, the amount of tax collected for such a journey shall be refunded to him or his agent in full by the carrier in the same manner as the fare is refunded.

(2) In any other case, a passenger or his agent claiming refund of any tax paid by him to the carrier may move an application to the carrier for refund of such tax before the expiry of a period of two years from the date of payment of the tax or the last date

of the journey in respect of which refund is being claimed, whichever is later.

(3) On receipt of an application under sub-rule (2), if the carrier is satisfied that the amount of tax paid has been erroneously collected and should be refunded, he may refund the amount to the passenger or his agent accordingly.

(4) Where a carrier, having paid into the treasury an amount by way of tax, finds that the same has been paid erroneously, he may prefer a claim by making an application for refund of such amount to the Assistant Collector of Customs, before the expiry of a period of two years from the date of payment of the tax in respect of which the refund is claimed.

(5) If on receipt of an application under sub-rule (4), the Assistant Collector of Customs is satisfied that the amount of tax erroneously paid should be refunded, he may make an order accordingly.

5. Non-payment or short payment of tax.—(1) Where any tax due has, for any reason, either not been paid or has not been paid in full by a passenger or his agent, the carrier may, within two years from the last date of the journey, make a demand in writing to the passenger or his agent to pay the amount.

(2) Where any tax collected by a carrier has, for any reason, either not been paid or has not been paid in full into the treasury under rule 6 or has been erroneously refunded under sub-rule (3) of rule 4, the Assistant Collector of Customs may, within a period of two years from the relevant date, serve notice upon the carrier concerned, requiring him to show cause why he should not pay the amount specified in the notice :

Provided that where any tax had not been paid or has not been paid in full or has been erroneously refunded by reason of collusion or any wilful misstatement or suppression of facts by the carrier, the provisions of this sub-rule shall have effect as if for the words "two years" the words "five years" were substituted.

(3) The Assistant Collector of Customs, after considering the representation, if any, made by the carrier on whom notice is served under sub-rule (1), shall determine the amount of tax to be paid by such carrier (not being in excess of the amount specified in the notice) and thereupon such carrier shall pay the amount so determined.

(4) For the purpose of sub-rule (2), the expression "relevant date" means—

(a) in case where the tax has not been paid, or has not been paid in full, the date of commencement

of the inland air journey to which the non-payment or the under-payment, as the case may be, relates, or, the date on which the carrier files the relevant return under these rules, whichever is later;

(b) in a case where the tax has erroneously been refunded under rule 4, sub-rule (4) of the date on which the refund was made.

6. Tax to be paid into the treasury.—The tax collected in any month by any carrier shall be paid by such carrier before the expiry of sixty days from the end of that month into the treasury :

Provided that the Collector of Customs may on sufficient cause being shown and having regard to the system of accounting adopted by any carrier allow such carrier to pay the tax within a further period not exceeding ninety days.

7. Return regarding tax collected, etc.—Every carrier required under rule 6 to pay the tax into the treasury shall file, in respect of every month before the expiry of sixty days from the end of that month, before the Collector of Customs, a return in that Form annexed to these rules, showing the amount of tax collected, amount refunded and the amount paid into the treasury :

Provided that the Collector of Customs may, having regard to the system of accounting adopted by any carrier allow such carrier to file such returns within a further period not exceeding ninety days.

8. Preservation of records by carrier.—Copies of all treasury challans or vouchers against which amounts collected as tax are paid into the treasury returns and all other documents relating to any inland journey shall be preserved by the carrier for a period of five years from the date on which such challans voucher return or other document was prepared :

Provided that the Collector of Customs may, by order in writing and for reasons to be recorded therein, require any carrier to preserve for a longer period than the said period of five years any such copy of challan, voucher, return or other document and the carrier against whom such order is made shall comply with such order.

9. Adjudication of penalties.—In every case in which any person is liable to penalty under section 46 of the Act, such penalty may be adjudged by the Assistant Collector of Customs.

10. Issue of show cause notice before levy of penalty.—No order imposing any penalty on any person shall be made unless such person—

(a) is given a notice in writing informing him of the grounds on which it is proposed to impose a penalty,

(b) is given an opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice, against the grounds for imposition of the penalty mentioned therein; and

(c) is given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

Provided that the notice referred to in clause (a) and the representation referred to in clause (b) may, at the instance of the person concerned, be oral.

11. Appeal.—(1) Any person aggrieved by any decision or order passed under the Act, or these rules, by the Assistant Collector of Customs may, within three months from the date of communication of such decision or order, appeal to the Collector of Customs (Appeals), Delhi :

Provided that the appellate authority may, if satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of three months, allow it to be presented within a further period of three months.

(2) The appellate authority may, after giving an opportunity to the appellant to be heard if he so desires, and after making such inquiry as may be necessary, pass such order as it thinks fit, confirming, modifying or annulling the decision or order appealed against :—

Provided that no order enhancing any penalty shall be passed by the appellate authority :

Provided further that where the appellate authority is of the opinion that any tax has not been paid or has not been paid in full into the treasury under rule 6 or has been erroneously refunded under sub-rule (4) of rule 4, no order directing the payment of such tax shall be passed unless the appellant is given notice within the time limit specified in sub-rule (2) of rule 5 to show cause against the proposed order.

12. Powers of revision of collector.—(1) Collector of Customs may, of his own motion or on the application of any aggrieved person, call for and examine the record of any proceedings in which an Officer of Customs subordinate to him has taken any decision or passed an order under the Act or these rules (not being an order passed in appeal under rule 11) for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any such decision or order and may pass such order thereon as he thinks fit.

Provided that no order enhancing any penalty shall be passed under this rule unless the person affected by the proposed order has been given a reasonable opportunity of showing cause against it.

Provided further that where the Collector of Customs is of the opinion that any tax has not been paid or has not been paid in full into the treasury under rule 6 or has been erroneously refunded under sub-rule (4) of rule 4, no order directing the payment of such tax shall be made unless the person affected by the proposed order is given notice to show cause against it within the time limit specified in sub-rule (2) of rule 5.

(2) No proceeding shall be initiated under this rule in respect of any decision or order after the expiry of a period of one year from the date of such decision or order.

(3) An Officer of Customs appointed as Additional Collector of Customs under section 4 of the Customs Act shall not be competent to exercise any powers of revision under this rule.

13. Revision by Central Government.—(1) The Central Government may, of its own motion or on the application of any person aggrieved by any order passed under rule 11 or rule 12, annul or modify such order.

(2) An application under sub-rule (1) shall be made within six months from the date of the communication to the applicant of the order against which the application is being made :

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause for presenting the application within the aforesaid period of six months, allow it to be presented within a further period of six months.

(3) No order enhancing any penalty shall be passed under this rule, unless, within one year from the date of the order sought to be annulled or modified, the person affected by the proposed order has been given a notice to show cause against it.

(4) Where the Central Government is of the opinion that any tax has not been paid or has not been paid in full into the treasury under rule 6 or has been erroneously refunded under sub-rule (4) of rule 4, no order directing the payment of such tax shall be made under this rule, unless the person affected by the proposed order has been given notice to show cause against it within the time limit specified in sub-rule (2) of rule 5.

14. Recovery of sums due to Government. — Where any tax demanded from any person or any penalty payable by any person under Chapter V of the Act is not paid, the Assistant Collector of Customs may prepare a certificate signed by him specifying the amount due and send it to the Collector of the district in which the said person owns property or

resides or carries on business and the said Collector, on receipt of such certificate, shall proceed to recover from the said person the amount specified thereunder as if it were an arrear of land revenue.

15 Power to inspect.—(1) Every Officer of Customs authorised in this behalf by a special or general Order of a gazetted Officer of Customs shall for the purpose of ascertaining whether or not the requirements of the Act or these rules have been complied with, at any reasonable time, have access to any premises of any carrier and have powers to require any person found therein, who for the time being is in charge thereof to produce of him for his inspection any books of accounts, returns or other documents and to furnish to him such other information as he may reasonably required for the purpose of ascertaining whether the requirements of the Act or these rules have been complied with.

(2) Every such officer shall also have free access to any aircraft engaged in the carriage of passengers on an inland journey and have powers to require any person on board to produce any of the aforesaid documents and to furnish the aforesaid information, for the said purpose.

16. Power to search aircraft or premises.—If an Officer of Customs not below the rank of an Assistant Collector of Customs has reason to believe that any document which in his opinion will be useful or relevant to any proceeding under the Act or these rules are secreted in any aircraft or any premises of a carrier, he may authorise any Officer of Customs or Central Excise Officers to search for such documents.

FORM

1. Name of the carrier
2. Month/period (to which this return pertains)
3. Gross Amount collected during the month/period
4. Amount refunded during the month/period
5. Net amount collected (3—4)
6. Amount paid into the treasury

[No. 4/IATT/89—F. No. 348/2/89-TRU]
K. L. DTTA, Dy. Secy.

